विभाग का नाम :– पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार,

विभाग का पता : तल–6, विंग–सी, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली – 110002

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या :– 120 (अतारांकित)
दिनांक :– 09 / 08 / 2017
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि सड़कों की सफाई के लिए पी. डब्लू. डी. द्वारा प्रयोग किए जा रहे मकेनिकल स्वीपर सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए निर्धारित मापदण्डों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। (ख) क्या यह सत्य है कि नियमानुसार मकेनिकल स्वीपर यूरो–4 के होने चाहिए, परन्तु पी.डब्लू.डी. द्वारा प्रयोग किए जा रहे स्वीपर यूरो–3 श्रेणी के हैं (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में केवल यूरो–4 के मकेनिकल स्वीपर का ही पंजीकरण हो सकता है, इसलिए इन स्वीपरों का पंजीकरण अन्य राज्यों में करवाकर दिल्ली लाया जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा राजस्व की हानि होती हैं	(क), (ख) एवं (ग) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 01 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल BS-IV मकेनिकल स्वीपर ही पंजीकृत हो सकते है। लो.नि.वि. से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदूषण को घटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने भी मेकैनिकल स्वीपर लगाने की योजना की थी। मशीनें लगाने की तुरन्त आवाश्यकता थी। इसलिए मार्केट में जो भी मशीनें उपलब्ध थीं उनको स्वीपिंग कार्य में लगा दिया गया था।
(घ) इसी प्रकार दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 300 टेंकर नेशनल परमिट प्राप्त कर यूरो–3 में चल रहे हैं और मकेनिकल स्वीपरों की भांति पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा राजस्व की हानि हो रही है, और	दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने हेतु टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई करता है। पूर्व में अधिकतर किराये के टैंकर यूरो–3 मानक के चल रहे थे। जिन्हें चरणबद्ध तरीके से यूरो–4 श्रेणी के नये टैंकरों में बदला जा रहा है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड में गत वर्षों में 250 यूरो–4 श्रेणी के टैंकर खरीदकर लगाए हैं और यूरो–3 श्रेणी के टैंकरों की संख्या कम कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जिन कॉलोनियों में पाईप की लाईन नहीं है, वहाँ नई पाईप लाईन बिछा कर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है एवं चरणबद्ध तरीके से यूरो–3 श्रेणी के टैंकरों को हटाया जा रहा है।
(ङ) क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए तथा सरकारी राजस्व हानि को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है?	उपरोक्तानुसार।

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Scientist
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi